

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 51/09

GCMS NO 2009/00019

1. जगन पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास (मृतक)
2. प्रेमराज पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
- किशनलाल पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. राजमल पुत्र मनसुखा जाति महाजन निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
2. कन्हैया पुत्र मनसुखा जाति महाजन निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास(मृतक)
 - 2/1. संतोष पुत्र कन्हैया
 - 2/2. उर्मिला पुत्री कन्हैया पत्नि हनुमान निवासी मलारना स्टेशन तहसील मलारना डूंगर
 - 2/3. सत्यनारायण पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी तहसील लालसोट
 - 2/4. मिटटू पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
 - 2/5. विनोद पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी(हजफ)
 - 2/6. पप्पू पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी (मृतक)
 - 2/6/1. पॉची बेवा पप्पू जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
 - 2/6/2. चन्दू पुत्र पप्पू जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
 - 2/6/3. मनीषा पुत्री पप्पू उम्र 16 वर्ष जरिये संरक्षिका माता पांची जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
 - 2/7. कुन्जीलाल पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
 - 2/8. श्रीमती रामेश्वरी पत्नि कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
 - 2/9. मिथलेश पुत्री कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी
3. बाबूलाल पुत्र मनसुखा जाति महाजन निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
4. भजन पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

रेसपो0

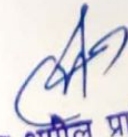
(अपील विरुद्ध मु0नं0 215/02 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.09 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामकिशोर शर्मा

अभिभाषक रेसपो0 श्री महेश चंद अग्रवाल

दिनांक 20.1.2025

निर्णय


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर




प्रस्तुत अपील अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.09 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोंड संख्या 1 ता 3 द्वारा दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नारौली चौड के ख०न० 2250 रकबा 18 विस्वा वादीगण के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 मे इन्द्राज खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत रूप से वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि का इन्द्राज सम्वत 2019 मे रहन मुर्तहन दर्ज करा लिया। सम्वत 2019 मे ख०न० 2250 का नम्बर 590 रकबा 18 विस्वा बना व वर्तमान बन्दोबस्त मे नम्बर 1767 रकबा 28 ऐयर कायम हुआ। वादग्रस्त भूमि पर रहन मुर्तहन का इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के व बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के करा लिया है जो गलत है। इस गलत इन्द्राज की आड मे प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 11.4.2000 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गई कि वादग्रस्त भूमि की फसल से लाभान्वित नही होने देगे। इस कारण वादीगण का दावा विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख०न० 1767 रकबा 28 ऐयर के वादीगण काबिज काश्कार खातेदार टीनेन्ट है। रिकार्ड मे इसी प्रकार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे ना ही भूमि मे जबरन प्रवेश नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पोंड संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पुत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।


अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोंड को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी तजबीज में अपीलांट के इस उज्र को स्वीकार किया है कि 2282,2283 की आराजीयात अपीलांट के दादा सुखराम पुत्र हरिकिशन के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रदर्श डी-1 से स्पष्ट है। इस रिकार्ड से ख०न० 2282 व 2283 रकबा 15 विस्वा की आराजीयात अपीलांट/प्रतिवादी की पैतृक आराजीयात होना स्पष्ट साबित होने पर भी उसको महत्व नही देकर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। एकीकरण मे उक्त नम्बरो के स्थान पर नया नम्बर 598 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा कायम किया है। रेस्पोंड 1 ता 3 के पिता की खातेदारी का नम्बर 2003 सेटलमेंट के समय 2250 रकबा 18 विस्वा था। जो एकीकरण 2019 मे 2250 का नम्बर बदलकर


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


590 बनाया गया तथा ख0न0 2282,2283 का रकबा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के रकबों से लगता हुआ था। इसलिए एकीकरण के समय 2282 व 2283 का रकबा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की आराजीयात में मिलाकर एक चक व एक नम्बर 598 बना दिया तथा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के खातेदारी की आराजीयात ख0न0 2250 से बने नवीन ख0न0 590 को अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 4 की खातेदारी में दर्ज कर दिया तथा इसी के अनुसार काबिज करा दिया। इस प्रकार एकीकरण के समय से ही अपीलान्ट ख0न0 590 पर वहैसियत खातेदार काबिज है। एकीकरण द्वारा जारी की गई पास बुक अवधि बन्दोबस्त सम्वत 2003 से 2022 में भूमि ख0न0 590 रकबा 18 विस्वा वाके तन ग्राम नारौली अपीलान्ट के पिता हरफूल वगै0 में नाम खातेदारी में दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जारी की गई पासबुको को अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि ख0न0 590 अपीलान्ट के पिता हरफूल की खातेदारी में रही है। फिर भी अपीलान्ट की जबाबदेही के विशेष विवरण के मद न0 18 को समझे बिना अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी तजबीज की है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने एकीकरण के समय अपीलान्ट की आराजी ख0न0 2282,2283 से बने ख0न0 595 को स्वयं को खातेदार व काबिज होना स्वीकार कर ख0न0 598 से बने नवीन नम्बर 1727,1728,1730,1736 को रामकन्या पत्नि केदार को बिक्री कर दिया। उक्त बिक्री का तथ्य स्पष्ट करता है कि रेस्पो0 व अपीलान्ट एकीकरण के अनुसार काबिज हो गये। उक्त तथ्य पत्रावली में होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने एकीकरण द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी के बदले में प्राप्त आराजी नम्बर 1767 की आराजी को रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की आराजी मानकर कानूनी भूल की है। तहसीलदार का कर्तव्य था कि एकीकरण के बदलाव का अधिनस्थ न्यायालय को ध्यान दिलाना चाहिए था ताकि अधिनस्थ न्यायालय को सच्चा न्याय करना संभव होता। रेस्पो0 की नियत में बेईमानी आ जाने के कारण उनकी खातेदारी की एवज में एकीकरण के अधिकारियों द्वारा अपीलान्ट की खातेदारी की जमीन दिये जाने के बाद भी उस जमीन को बेच कर उससे लाभ अर्जित कर लिया गया। अपीलान्ट की एकीकरण अधिकारियों द्वारा बदले में दी जमीन को हड़प करने के लिए दावा कर दिया गया। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा बिक्री की गई जमीनो का क्रेता के नाम नामा0 खोला हुआ है जिसका इन्द्राज जमाबंदी में दर्ज है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को रेस्पो0 ने अदालत में छिपाकर धोका देकर अपने पक्ष में निर्णय कराया है। अपीलान्ट विवादित आराजीयात पर वहैसियत खातेदार लीगल व फिजीकली काबिज है। रेस्पो0 को इन्द्राज दुरुस्ती कराने का किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में तर्क दिया कि आराजी ख0न0 2250 रकबा 15 विस्वा वादीगण/रेस्पो0 के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जिसे गलत रूप से अपीलान्ट/प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियों से मिलकर गलत रूप से भूमि का इन्द्राज सम्वत


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

2019 में रहन मुर्तहीन दर्ज करवा लिया गया। सम्वत 2019 में ख0न0 2250 का नम्बर 590 रकबा 18 विस्वा बना व वर्तमान बन्दोबस्त में नम्बर 1767 रकबा 28 ऐयर कायम किया है। उक्त आराजीयात पर रहन मुर्तहीन का इन्द्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के कराया गया है जो विधि विरुद्ध होने से निरस्त योग्य था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में 7 तनकीयात कायम की गई। जिसमें तनकी संख्या 1 व 2 वादी/रेस्पो0 के पक्ष में निर्णित की गई है जिसमें नकल जमाबंदी सम्वत 2016-19 प्रदर्श 1 के अनुसार भूमि ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा मनसुखा पुत्र गल्ला महाजन सा0देह की खातेदारी में दर्ज होना अंकित किया है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 प्रदर्श 8 व नकल खसरा गिरदावरी 2017 से 2018 प्रदर्श 7 के अनुसार ख0न0 2250 पर खातेदार मनसुखा की काश्त दर्ज है। इस प्रकार आराजी ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा वादीगण/रेस्पो0 के पिता मनसुखा की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित होता है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 में भूमि को गलत रूप से एकीकरण द्वारा रहन मुर्तहीन का इन्द्राज करने का तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। राजस्व रिकार्ड में भूमि वर्तमान में रहन मुर्तहीन होना भी राजस्व रिकार्ड से साबित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं विश्लेषण से साबिक नम्बर 2250 को वादीगण/रेस्पो0 के पिता की आराजीयात माना गया है। जो राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट साबित है। एकीकरण के दौरान विवादित आराजीयात अपीलान्त/प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से खातेदारी में दर्ज कर रहन मुर्तहीन कर दी गई थी। जिसे वादीगण/रेस्पो0 सही कराने का अधिकार रखने के कारण ही दुरुस्त कराने का अधिकारी होने से ही अधिनस्थ न्यायालय में वाद पत्र पेश कर विधि अनुसार वाद पत्र डिक्री कराया गया है। जो विधिक रूप से सही होने से अपीलान्त की अपील योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील खारिज फरमाई जावे।


उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा की खातेदारी मनसुखा बल्द गलजी महाजन के नाम दर्ज है। नकल गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 प्रदर्श 7 व 2017 से 2018 प्रदर्श 8 में मनसुखा की काश्त दर्ज है। तनकी संख्या 1 गलत रूप से वादी के पक्ष में तय की गई है क्योंकि एकीकरण में चक बनाने के हिसाब से भूमि दी गई थी ना ही कब्जे के हिसाब से अर्थात् एकीकरण में वादी की भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी में तथा प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण की खातेदारी में दे दी गई। जिसे वादीगण को प्रतिवादीगण की भूमि पर एकीकरण ने ख0न0 590 कायम कर दे दी गई तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि ख0न0 2282 व 2283 देकर उसका एकीकरण द्वारा ख0न0 598 कायम कर एक चक कर दिया गया जिनके दौरान सेटलमेंट नये ख0न0 कायम कर खातेदारी एकीकरण खसरा नम्बर अनुसार दर्ज कर दी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आराजी की कमी पूर्ति बाबत निर्णय किया है वह आराजी एकीकरण से पूर्व में एकीकरण के उद्देश्य से एक दूसरे खातेदारान की आराजीयात मिलाकर नये रकबे एवं खसरे तैयार किये गये हैं जिनको अब


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपीलांत की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 215/02 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.09 को अपास्त किया जाता है। विवादित आराजीयात के बाबत यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की अपील में किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो तो किये गये परिवर्तन निरस्त किये जावे तथा विवादित आराजीयात की दावे से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।


राजस्व अपील अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी